The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Year-7 Volume: IV, October-December, 2025
Issue-28 ISSN: 2582-1296 (Online)
Website: www.theasianthinker.com **Email**: asianthinkerjournal@gmail.com

21. नई शिक्षा नीति 2020 एवं उच्च शिक्षण की समस्याएँ, कारण एवं उपयोगिता

मनीषा सक्सेना
अधिष्ठाता
शिक्षा एवं कौशल विकास अध्ययनशाला, ब्राउस
डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)

आकाश डाबोड़े
विजिटिंग फैकल्टी
शिक्षा एवं कौशल विकास अध्ययनशाला, ब्राउस
डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)

शोध सार

विश्वगुरू के लक्ष्य की ओर अग्रेषित भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है, जिसमें प्रतिवर्ष लाखों विद्यार्थी नामांकन लेते हैं। उच्च शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है, बल्कि यह राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समय के साथ–साथ समाज, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आए परिवर्तनों ने शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता उत्पन्न की। इसी संदर्भ में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई। जिसके कई सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव हैं विशेषकर विद्यार्थी वर्ग पर बहुत अधिक प्रभाव हुआ है। प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य भारतीय शिक्षा नीति के संदर्भ में उच्च शिक्षा विद्यार्थियों की समस्याओं, उनके कारणों तथा नई शिक्षा नीति की उपयोगिता का विस्तृत वर्णन करना है। सामान्यतः उच्च शिक्षा के विद्यार्थी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, भाषाई, तकनीकी एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 समाधान हेतु शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार तथा समावेशी दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास करती है।

प्रमुख शब्द- नई शिक्षा नीति 2020, उच्च शिक्षण की समस्याएँ**,** कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं बौद्धिक प्रगति का मूल आधार होती है। यह न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है, बल्कि उसे एक जिम्मेदार नागरिक, अनुशासन, कुशल कार्यकर्ता और संवेदनशील प्राणी का निर्माण कर तैयार करती है। विशेष रूप से उच्च शिक्षा किसी देश के मानव संसाधन विकास, वैज्ञानिक प्रगति, तार्किकता, कौशल,तकनीकी नवाचार और लोकतांत्रिक चेतना को सशक्त करती है।

भारत जैसे देश जो विशाल, सांस्कृतिक एवं विविधतापूर्ण जनसंख्या के कारण उच्च शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, यहाँ सामाजिक–आर्थिक , सांस्कृतिक असमानताएँ, क्षेत्रीय विषमताएँ तथा शैक्षणिक अवसरों में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीय संविधान अमूल्य विधि हैं जो समस्त जो समस्त जनसंख्या के प्रति उत्तरदायित्व का बोध का बोध कराता है

विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और शोध संस्थानों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। इसके बावजूद, यह सत्य है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, उपयोगिता और समानता वर्तमान में एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। आज उच्च शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह रोजगार, सामाजिक गतिशीलता, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ चुकी है। ऐसे में यह अपेक्षा की जाती है कि उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को न केवल विषयगत ज्ञान प्रदान करे, बल्कि उनमें कौशल, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान क्षमता, नवाचार की प्रवृत्ति और नैतिक मूल्यों का भी विकास करे। किंतु व्यवहार में देखने पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली इस लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने में अभी भी संघर्ष कर रही है। वर्तमान शिक्षा नीति के उद्देश्यों की पूर्ति प्रत्येक कारकों के कारण आवश्यक हैं, विशेषकर विद्यार्थी वर्ग।

माना जाता हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएँ केवल शैक्षणिक ही नहीं होतीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, भाषाई, तकनीकी और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी विद्यार्थियों को प्रभावित करती हैं।आज उच्च शिक्षा विद्यार्थियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। इन समस्याओं का सीधा प्रभाव विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि, आत्मविश्वास और भविष्य की संभावनाओं पर पड़ता है।

NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को अधिक लचीला, समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी बनाना है। इस नीति के अंतर्गत बहुविषयक शिक्षा, कौशल आधारित पाठ्यक्रम, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन, डिजिटल शिक्षा का विस्तार और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। यह नीति इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि, क्षमता और परिस्थिति अलग होती है, अतः शिक्षा व्यवस्था भी लचीली और विद्यार्थी–केंद्रित होनी चाहिए।

हालाँकि, किसी भी नीति की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। नई शिक्षा नीति के प्रावधान तभी सार्थक सिद्ध होंगे जब वे उच्च शिक्षा विद्यार्थियों की वास्तविक समस्याओं का समाधान कर सकें। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उच्च शिक्षा विद्यार्थियों की समस्याओं को गहराई से समझा जाए, उनके कारणों का विश्लेषण किया जाए और यह देखा जाए कि नई शिक्षा नीति इन समस्याओं के समाधान में किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

इसी संदर्भ में प्रस्तुत शोध–पत्र "नई शिक्षा नीति 2020 एवं उच्च शिक्षण की समस्याएँ, कारण एवं उपयोगिता " विषय पर केंद्रित है। इस अध्ययन का उद्देश्य भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना, विद्यार्थियों को होने वाली प्रमुख समस्याओं की पहचान करना, उन समस्याओं के मूल कारणों को समझना तथा नई शिक्षा नीति की उपयोगिता का मूल्यांकन करना है। यह शोध–पत्र न केवल शिक्षा नीतियों के अध्ययन में सहायक होगा, बल्कि शिक्षकों, शोधार्थियों, नीति–निर्माताओं और विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।

नई शिक्षा नीति 2020 : अवधारणा एवं दृष्टिकोण

The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Year-7 Volume: IV, October-December, 2025
Issue-28 ISSN: 2582-1296 (Online)
Website: www.theasianthinker.com **Email**: asianthinkerjournal@gmail.com

नई शिक्षा नीति 2020 भारत की तीसरी प्रमुख शिक्षा नीति है। यह नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इसका मूल दर्शन यह है कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन न होकर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का माध्यम बने। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा को बहुविषयक, शोध–आधारित और कौशल–केंद्रित बनाने पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति में शिक्षा को अधिक लोकतांत्रिक, समावेशी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया है।नीति के प्रमुख प्रावधानों में मल्टीपल एंट्री–एग्जिट सिस्टम, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, डिजिटल शिक्षा का विस्तार, अनुसंधान को बढ़ावा और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा शामिल हैं।

विगत दो दशकों में वैश्वीकरण, उदारीकरण और तकनीकी क्रांति के कारण शिक्षा के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। ज्ञान अब केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल माध्यमों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे साधनों के माध्यम से तेजी से विकसित हो रहा है। ऐसे परिवेश में यदि शिक्षा प्रणाली समयानुकूल न हो, तो वह विद्यार्थियों को समाज और बाजार की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार नहीं कर सकती। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में भी यह आलोचना की जाती रही है कि पाठ्यक्रम पुराने हैं, शिक्षण विधियाँ पारंपरिक हैं और उद्योग तथा शिक्षा के बीच समन्वय का अभाव है।

इन्हीं सभी चुनौतियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। यह नीति लगभग 34 वर्षों बाद लाई गई एक व्यापक और दूरदर्शी नीति है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार करना है। नई शिक्षा नीति केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा में भी व्यापक परिवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है।

उच्च शिक्षा में आने वाली समस्याएँ

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में नामांकन की संख्या बढ़ने के बावजूद विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के दौरान अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएँ केवल शैक्षणिक तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, भाषाई, तकनीकी, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक स्तर पर भी विद्यार्थियों के जीवन को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं की जड़ें संरचनात्मक कमियों, सामाजिक–आर्थिक असमानताओं और नीति–क्रियान्वयन की कमजोरियों में निहित हैं।

आर्थिक समस्या उच्च शिक्षा विद्यार्थियों की सबसे गंभीर और व्यापक समस्या मानी जाती है। भारत में उच्च शिक्षा की लागत निरंतर बढ़ रही है, विशेषकर निजी विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में। सरकारी संस्थानों में सीमित सीटों के कारण अधिकांश विद्यार्थियों को निजी संस्थानों का सहारा लेना पड़ता है, जहाँ शुल्क सामान्य परिवारों की आर्थिक क्षमता से कहीं अधिक होता है।

शिक्षा शुल्क के अतिरिक्त विद्यार्थियों को छात्रावास शुल्क, भोजन, परिवहन, पुस्तकों, अध्ययन सामग्री, इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों पर भी भारी खर्च करना पड़ता है। ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी इन खर्चों को वहन करने

में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें शिक्षा बीच में छोड़नी पड़ती है या पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार करना पड़ता है।आर्थिक असुरक्षा का सीधा प्रभाव विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। निरंतर आर्थिक दबाव के कारण वे तनाव, चिंता और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहते हैं, जिससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धि प्रभावित होती है।

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों प्रवेश की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि विद्यार्थी हो प्रत्येक समय प्रवेश प्रवेश प्रक्रिया में कठिनाई एवं समस्या का सामना करता है जिसे उसमें आरंभिक तौर पर ही निरस्तता एवं उदासीनता जन्म ले लेती है जो नकारात्मक भाव को दर्शाता है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की एक प्रमुख समस्या इसकी अकादमिक संरचना से जुड़ी हुई है। आज भी अनेक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पुराने और अप्रासंगिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं, जो वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक आवश्यकताओं से मेल नहीं खाते।

शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में रटने वाली पद्धति पर अत्यधिक निर्भरता पाई जाती है, जिससे विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच का विकास नहीं हो पाता। व्यावहारिक शिक्षा, फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट आधारित अधिगम और शोध कार्यों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता।इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन प्रणाली भी कई बार पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं होती। केवल परीक्षा–आधारित मूल्यांकन विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमता और कौशल का सही आकलन नहीं कर पाता, जिससे उनमें असंतोष और निराशा की भावना उत्पन्न होती है। विद्यार्थियों को ग्रंथालय का समय नहीं मिल पाता है किताबें पढ़ने की आदत निरंतर खत्म होती जा रही है यह प्रिंट मीडिया एवं उनसे मिलने वाले ज्ञान के अनुभव के प्रति कमी को दिखाता है।

अधोसंरचना से संबंधित समस्या

उच्च शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध भौतिक और शैक्षणिक संसाधनों की असमानता एक गंभीर समस्या है। शहरी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित संस्थानों की तुलना में ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों के कॉलेजों में प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, स्मार्ट कक्षाओं और तकनीकी उपकरणों का अभाव पाया जाता है।इसके साथ ही योग्य, प्रशिक्षित और स्थायी शिक्षकों की कमी भी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अतिथि शिक्षकों पर अत्यधिक निर्भरता से शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में निरंतरता नहीं रह पाती। संसाधनों की यह कमी विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता को कमजोर करती है।

जो सुख सुविधाएं अधोसंरचना के माध्यम से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में उपलब्ध है जैसे की शौचालय आदि की व्यवस्था वह भी अनियमितता एवं अव्यवस्था के चलते या तो साफ सुथरे नहीं है एवं उनमें स्वच्छता का अभाव है या उपयोग योग्य नहीं है यह स्थिति विद्यार्थियों के समग्र विकास में बाधा उत्पन्न करता है

डिजिटल डिवाइड एवं आधुनिक तकनीक से संबंधित समस्याएँ

डिजिटल शिक्षा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अनिवार्य अंग माना जा रहा है, किंतु भारत में डिजिटल संसाधनों की समान उपलब्धता नहीं है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थी इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन, लैपटॉप और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण ऑनलाइन शिक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा पाते।कोविड–19 महामारी के दौरान

यह समस्या और भी स्पष्ट हो गई, जब अनेक विद्यार्थी तकनीकी संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित रह गए। डिजिटल डिवाइड ने शिक्षा में पहले से मौजूद असमानताओं को और गहरा कर दिया।

उच्च शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाना है, किंतु वर्तमान व्यवस्था इस उद्देश्य को पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रही है। पाठ्यक्रमों और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच स्पष्ट अंतर देखा जाता है।कई विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करने के बाद भी आवश्यक तकनीकी, संचार, समस्या समाधान और व्यावसायिक कौशल से वंचित रह जाते हैं। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और उद्योग–संस्थान सहयोग के अवसरों की कमी के कारण विद्यार्थी वास्तविक कार्य–अनुभव प्राप्त नहीं कर पाते। इसका परिणाम शिक्षित बेरोजगारी के रूप में सामने आता है।

विद्यार्थी आज अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, परीक्षा दबाव, करियर अनिश्चितता और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। निरंतर तुलना, असफलता का भय और भविष्य को लेकर अनिश्चितता विद्यार्थियों में तनाव, अवसाद और चिंता जैसी समस्याएँ उत्पन्न करती हैं।अनेक उच्च शिक्षा संस्थानों में परामर्श सेवाओं और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे समस्या और गंभीर हो जाती है। यह स्थिति न केवल विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है, बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में भी बाधा उत्पन्न करती है।

भारतीय उच्च शिक्षा विद्यार्थियों की समस्याएँ अचानक उत्पन्न नहीं हुई हैं, बल्कि इनके पीछे अनेक संरचनात्मक, नीतिगत, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी कारण निहित हैं। जब तक इन कारणों को गहराई से नहीं समझा जाएगा, तब तक समस्याओं के स्थायी समाधान की कल्पना भी संभव नहीं है। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की कठिनाइयाँ दरअसल शिक्षा व्यवस्था की दीर्घकालीन कमजोरियों का परिणाम हैं।उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का अधिकांश समय कक्षाओं, असाइनमेंट, परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में व्यतीत हो जाता है। खेल, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, कला, संगीत और सामाजिक सहभागिता के लिए पर्याप्त अवसर न मिलने से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास बाधित होता है

मनोरंजन समय की उपलब्धता भी बहुत सीमित रह गई जिससे विद्यार्थियों में रचनात्मक गतिविधियों की कमी छात्रों में एकरसता, मानसिक थकान और अध्ययन से विरक्ति को जन्म देती है। विद्यार्थियों में नई शिक्षा नीति 2020 में अधिक विषयों के पाठ्यक्रम ,शिक्षक तथा समय के मध्य सामंजस्य भी एक बड़ी समस्या है वह नियमित शिक्षण नहीं करना चाहते उनके द्वारा स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा में एक कल्पना का दौर शुरू होता है जो उनको शिक्षा के प्रति रुझान एवं कक्षाओं के संचालन के प्रति रुझान में कमी को दिखाता है

नीतिगत एवं विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित कारण

उच्च शिक्षा से संबंधित समस्याओं का एक प्रमुख कारण नीतियों और उनके क्रियान्वयन के बीच का अंतर है। यद्यपि समय–समय पर शिक्षा सुधार हेतु अनेक नीतियाँ और योजनाएँ बनाई गईं, लेकिन उनका प्रभावी और समान क्रियान्वयन नहीं हो पाया।

भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित नियामक संस्थाओं जैसे UGC, AICTE, विश्वविद्यालय प्रशासन आदि की संरचना जटिल और केंद्रीकृत रही है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और संस्थानों को आवश्यक स्वायत्तता

The Asian Thinker

नहीं मिल पाती। परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम अद्यतन, नवाचार और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सुधार समय पर नहीं हो पाते।इसके अतिरिक्त, शिक्षा नीतियों का निर्माण तो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, लेकिन उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संस्थानों पर होती है। संसाधनों और प्रशासनिक क्षमता में असमानता के कारण नीति का लाभ सभी विद्यार्थियों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाता।

आर्थिक एवं सामाजिक असमानता

भारतीय समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता उच्च शिक्षा की समस्याओं का एक मूल कारण है। गरीबी, बेरोजगारी, निम्न पारिवारिक आय और सामाजिक पिछड़ापन विद्यार्थियों की शिक्षा यात्रा को कठिन बना देते हैं।ग्रामीण, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित वर्गों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा में प्रवेश तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे निरंतर शिक्षा जारी नहीं रख पाते। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियाँ, घरेलू कार्य और सामाजिक अपेक्षाएँ भी उनके अध्ययन में बाधा उत्पन्न करती हैं।इस असमानता के कारण उच्च शिक्षा में ड्रॉपआउट दर अधिक देखी जाती है, जो सामाजिक विकास के लिए एक गंभीर चुनौती है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में संस्थानों के बीच अत्यधिक असमानता पाई जाती है। कुछ केंद्रीय और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जबकि अधिकांश राज्य स्तरीय और ग्रामीण महाविद्यालय बुनियादी संसाधनों से भी वंचित हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 के बाधक कारण

प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, शोध सुविधाओं, तकनीकी उपकरणों और योग्य शिक्षकों की कमी विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। संसाधनों की यह असमानता विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं में भी अंतर उत्पन्न करती है।डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के बावजूद, भारत में तकनीकी अवसंरचना का विकास समान रूप से नहीं हुआ है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है और डिजिटल उपकरणों की लागत सामान्य परिवारों के लिए अधिक है।

इसके साथ ही, डिजिटल साक्षरता की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कई विद्यार्थी तकनीक का उपयोग केवल मनोरंजन तक सीमित रखते हैं और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उसका प्रभावी उपयोग नहीं कर पाते। यह स्थिति डिजिटल शिक्षा को अवसर की बजाय बाधा बना देती है। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों और रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के बीच तालमेल की कमी विद्यार्थियों की प्रमुख समस्याओं का कारण है। अनेक पाठ्यक्रम केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित हैं और उनमें व्यावहारिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्योग अनुभव को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। इस कारण विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करने के बाद भी रोजगार के लिए तैयार नहीं हो पाते। यह स्थिति शिक्षित बेरोजगारी को जन्म देती है, जो युवाओं में निराशा और असंतोष का कारण बनती है।

अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व उच्च शिक्षा में एक संरचनात्मक समस्या बन चुका है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से आने वाले विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करना कठिन होता है। भाषाई बाधा के कारण विद्यार्थी न तो

The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Year-7 Volume: IV, October-December, 2025
Issue-28 ISSN: 2582-1296 (Online)
Website: www.theasianthinker.com **Email**: asianthinkerjournal@gmail.com

विषय को पूरी तरह समझ पाते हैं और न ही कक्षा में सक्रिय भागीदारी कर पाते हैं। इससे उनमें आत्महीनता की भावना उत्पन्न होती है, जो शैक्षणिक और मानसिक दोनों स्तरों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।

उच्च शिक्षा संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य को अभी भी पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। परामर्श केंद्रों, प्रशिक्षित काउंसलरों और सहायता तंत्र की कमी के कारण विद्यार्थी अपनी समस्याओं को साझा नहीं कर पाते। प्रतिस्पर्धा, असफलता का भय, करियर अनिश्चितता और पारिवारिक दबाव धीरे–धीरे गंभीर मानसिक समस्याओं का रूप ले लेते हैं, जिनका समय पर समाधान न होना अत्यंत चिंताजनक है।

नई शिक्षा नीति 2020 की उपयोगिता एवं एवं भविष्यगामी संभावनाएं

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में व्याप्त समस्याओं के समाधान हेतु नई शिक्षा नीति 2020 को एक दूरदर्शी और संरचनात्मक सुधार नीति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह नीति केवल पाठ्यक्रम या परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य, स्वरूप और प्रक्रिया को मूल रूप से बदलने का प्रयास करती है। नई शिक्षा नीति की उपयोगिता इस बात में निहित है कि यह उच्च शिक्षा विद्यार्थियों की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, तकनीकी और मानसिक समस्याओं को एक समग्र दृष्टिकोण से संबोधित करती है। नई शिक्षा नीति 2020 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान बहुविषयक शिक्षा है। पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थी को एक ही विषय या संकाय तक सीमित रहना पड़ता था, जिससे उसकी सोच और संभावनाएँ सीमित हो जाती थीं।बहुविषयक शिक्षा के माध्यम से अब विद्यार्थी विज्ञान, कला, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों का संयोजन कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता और नवाचार का विकास होता है।

उच्च शिक्षा विद्यार्थियों की यह समस्या रही है कि वे डिग्री तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन की जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं हो पाते। बहुविषयक शिक्षा इस कमी को दूर करती है और विद्यार्थियों को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मल्टीपल एंट्री–एग्जिट सिस्टम और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक कारणों से अपनी शिक्षा बीच में छोड़ने को विवश हो जाते हैं।इस प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को अस्थायी रूप से रोककर बाद में पुनः आरंभ कर सकते हैं। इससे ड्रॉपआउट की समस्या में कमी आएगी और शिक्षा अधिक समावेशी बनेगी। यह प्रावधान विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है।

उच्च शिक्षा विद्यार्थियों की सबसे गंभीर समस्या रोजगार की कमी रही है। नई शिक्षा नीति 2020 इस समस्या के समाधान हेतु कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष बल देती है।नीति के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, उद्यमिता विकास और उद्योग–संस्थान सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। इससे विद्यार्थी केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त करते हैं।कौशल विकास से न केवल रोजगार के

अवसर बढ़ेंगे, बल्कि विद्यार्थी स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर भी प्रेरित होंगे, जिससे शिक्षित बेरोजगारी की समस्या में कमी आएगी।

यह नीति डिजिटल शिक्षा को उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग मानती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लैब्स और ब्लेंडेड लर्निंग के माध्यम से शिक्षा को अधिक सुलभ और लचीला बनाया गया है।डिजिटल शिक्षा की उपयोगिता विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए है, जहाँ भौतिक संसाधनों की कमी है। हालाँकि डिजिटल डिवाइड एक चुनौती है, फिर भी नीति के माध्यम से डिजिटल अवसंरचना के विस्तार और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में शोध संस्कृति को मजबूत करना है।अब तक भारतीय उच्च शिक्षा में शोध को सीमित महत्व दिया जाता था, जिससे नवाचार और ज्ञान सृजन में कमी देखी गई। NRF के माध्यम से विद्यार्थियों और शिक्षकों को शोध के लिए वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और संस्थागत समर्थन मिलेगा। इससे भारत को ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में सहायता मिलेगी।

नई शिक्षा नीति उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं और मातृभाषा को प्रोत्साहित करती है। इससे उन विद्यार्थियों को लाभ होगा, जो अंग्रेजी भाषा के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।मातृभाषा में अध्ययन से विषय की समझ गहरी होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होता है। यह प्रावधान शिक्षा को अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनाता है।

इसके माध्यम से वंचित वर्गों, महिलाओं, दिव्यांग विद्यार्थियों और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए विशेष प्रावधान करती है। छात्रवृत्ति, छात्र सहायता, डिजिटल संसाधन और लचीली शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है।यह नीति सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और उच्च शिक्षा को केवल विशेष वर्ग तक सीमित न रखकर समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाने का प्रयास करती है। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र विकास पर भी ध्यान दिया गया है। परामर्श सेवाएँ, सह–पाठ्यक्रम गतिविधियाँ और विद्यार्थी–केंद्रित शिक्षण पद्धतियाँ मानसिक दबाव को कम करने में सहायक सिद्ध होती हैं।इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण और जीवन कौशल का विकास होता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रही है जहाँ एक ओर शिक्षा का तीव्र विस्तार हुआ है, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता, समानता और उपयोगिता से संबंधित गंभीर चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को आर्थिक दबाव, शैक्षणिक असंगति, संसाधनों की कमी, डिजिटल असमानता, भाषाई बाधाएँ, रोजगार–असुरक्षा तथा मानसिक तनाव जैसी बहुआयामी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्याएँ केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती हैं।

The Asian Thinker

अध्ययन में यह भी स्पष्ट हुआ कि विद्यार्थियों की समस्याओं के पीछे नीतिगत कमियाँ, सामाजिक–आर्थिक असमानताएँ, शिक्षा संस्थानों में संसाधनों की असमान उपलब्धता, पाठ्यक्रम और उद्योग के बीच बढ़ती खाई तथा मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी जैसे कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। जब तक इन कारणों को समग्र दृष्टिकोण से नहीं समझा जाएगा, तब तक उच्च शिक्षा में सुधार अधूरा ही रहेगा।

इस संदर्भ में नई शिक्षा नीति 2020 को भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी पहल के रूप में देखा जा सकता है। यह नीति बहुविषयक शिक्षा, लचीली अकादमिक संरचना, कौशल–आधारित पाठ्यक्रम, डिजिटल शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार तथा सामाजिक समावेशन पर बल देकर उच्च शिक्षा को अधिक उपयोगी और विद्यार्थी–केंद्रित बनाने का प्रयास करती है।

हालाँकि, यह भी निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी नीति की सफलता उसके प्रभावी, समान और सतत क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यदि नई शिक्षा नीति को पर्याप्त संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों, तकनीकी अवसंरचना और संस्थागत सहयोग के साथ लागू किया जाए, तो यह उच्च शिक्षा विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस प्रकार, नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय उच्च शिक्षा को गुणवत्ता, समानता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में आगे ले जाने की क्षमता रखती है।

संदर्भ

1. Agarwal, J. C. (2010). *Indian education system and educational policy*. Shipra Publications.
2. All India Council for Technical Education. (2021). *Annual report on technical education*. AICTE.
3. Altbach, P. G. (2014). *Global perspectives on higher education*. Johns Hopkins University Press.
4. Government of India. (1966). *Education and national development: Report of the Education Commission (1964–66)* (Kothari Commission). Ministry of Education.
5. Government of India. (2020). *National education policy 2020*. Ministry of Education.
6. Kumar, R. (2014). *Development of education in India: Problems and challenges*. Atlantic Publishers.
7. Kumar, S. (2019). Employability issues among Indian graduates. *Journal of Higher Education and Policy Studies, 7*(1), 23–34.
8. Ministry of Education, Government of India. (2022). *All India Survey on Higher Education (AISHE) 2020–21*. Government of India.

The Asian Thinker

9. Mishra, P. (2020). Digital divide and online education in India. *Indian Journal of Educational Research, 9*(3), 61–70.
10. National Knowledge Commission. (2009). *Report on higher education*. Government of India.
11. Pandey, R. S. (2015). *Higher education: Concept, structure and challenges*. Lokbharti Prakashan.
12. Singh, A., & Sharma, R. (2018). Challenges of higher education in India. *International Journal of Educational Studies, 5*(2), 45–52.
13. Tilak, J. B. G. (2015). *Education in India: Challenges and opportunities*. Orient Blackswan.
14. UNESCO. (2017). *Education for sustainable development goals: Learning objectives*. UNESCO Publishing.
15. Verma, S. (2021). Impact of National Education Policy 2020 on higher education system. *International Journal of Multidisciplinary Research, 6*(4), 112–120.
16. University Grants Commission. (2019). *Higher education in India: Issues, concerns and reforms*. UGC.

The Asian Thinker